ing utilisation of only flow supplies of the rivers was Rs. 66.46 crores in 1957. After 1960, the scope of the project was revised and it's implementtion taken up in two stages Stage I of the Canal Project was aapproved in 1970 for Rs. 110.20 crores to provide irrigation facilities to an area of 5.30 lakh ha. This has since been completed and an expendiutre of Rs. 270.90 crores incurred. Stage II of the project was approved in 1972 for Rs. 89.12 crores to provide irrigation to 6.07 lakh ha. On the suggestion of the National Commission on Agriculture it was decided to extend the benefits of irrigation to certain list areas and the scope of Stage II underwent further revisions. The scope of Stage II now under execution, to provide irrigation facilities to an area of 10.12 lakh ha. (including an area of 3.12 lakh ha. under lift) was approved in April, 1987 for Rs. 934.24 crores. The expenditure incurred till Augost 1991 on Stage II is Rs. 454.63 crores. The State Government have not finalised the revised etimate for canal and area development works.

राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष

*31. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 को राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने लोगों को साक्षर बनाया गया तथा चालू वर्ष के लिये इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार साक्षरता को ग्रामीण रोजगार, कृषि विकास कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के कार्यक्रमों से जोड़ने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) वर्ष 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया गया था।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा में नामांकित किये गये राज्यवार व्यक्तियों को बताई गई संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**नीचे देखिये**) । इसके अतिरिक्त, उस वर्ष के दौरान, लगभग 2 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिये 42 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान भी प्रारम्भ किये गये थे । चालू वित्तीय वर्ष में 23 अतिरिक्त जिलों जिसकी लगभग एक करोड़ जनसंख्या निरक्षर है, में पूर्व साक्षरता अभियान प्रारम्भ कर दिये गये हैं । यद्यपि चालू वर्ष के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि उन 65 जिलों, जिनमें पूर्ण साक्षरता अभियान पहले से ही चल रहे हैं के अलावा 15-20 और जिलों को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, अन्य चालू कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन , क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के अनुसार जारी रखा जायेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान

करना है, जिसका अर्थ है कि साक्षरता कार्यक्रमों को विकास संबंधी अन्य विभागों के कार्यक्रमों के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा जाना चाहिये । अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि सफल साक्षरता कार्य-क्रमों के अन्तर्गत लाभग्राहियों के जीवन-स्तर व कार्य-शर्तों में चहुंमुखी सुधार हुआ है।

(ङ) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिये निर्धारित व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सेक्टर में क्रमश: 120.00 करोड़ रु० और 287.30 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में से विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि प्रत्येक मामले में अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं पर निर्भर करेगी । इसके अतिरिक्त, वर्ष 1991–92 के लिये राज्य सेक्टर में प्रौढ़ शिक्षा के लिये 58.75 करोड़ रु० और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 49.43 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 1990–91 के दौरान नामांकित व्यक्ति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	695642
2.	अरुणाचल प्रदेश	34651
3.	असम	367300
4.	गोवा	941254
5.	गुजरात	6197
6.	बिहार	432927
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	53011
9.	जम्मू और काश्मीर	75357
10.	कर्नाटक	323300
11.	केरल	100% शत-प्रतिशत साक्षर
12.	मध्य प्रदेश	724907
13.	महाराष्ट्र	843306
14.	मणिपुर	59241

1	2	3
15.	मेघालय	5326
16.	मिजोरम	28799
17.	नागालैंड	15541
18.	उड़ीसा	850000
19.	पंजाब	157848
20.	राजस्थान	510555
21.	सिक्किम	6963
22.	तमिलनाडु	681890
23.	त्रिपुरा	48601
24.	उत्तर प्रदेश	1996897
25.	पश्चिम बंगाल	209351
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9017
27.	चंडीगढ़	7642
28.	दादर और नगर हवेली	4500
29.	दमन और दीव	1135
30.	दिल्ली	66913
31.	लक्ष द्वीप	1019
32.	पांडिचेरी	6683

Theft of telephone cables in the capital

*32. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the telephone services have been paralysed in the capital to a large extent during the few months due to thefts of telephone cables;

(b) whether the MTNL has alleged police apathy over the cable thefts in the Capital; and

(c) if so, what are the details thereof and projects made in solving the thefts?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir, telephone service in some parts of the capital have been paralysed at times affecting a large number of customers due to telephone cable thefts during the past several months.

(b) and (c) No, Sir. Delhi Police in general and officers in particular have been cooperative. MTNL has taken measures like double locking of manhole covers on duct routes, laying of cable in concrete on open culverts and ex-